



एकनाथ शिंदे - बड़े पावर प्ले की रणनीति में जुटे
 पेज- 2

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार पत्र

# न्यूज वाणी



www.newswni.in

एआईएमआईएम का सनगांव वाई से प्रत्याशी घोषित
 पेज-6

वर्ष : 15 अंक : 32

मंगलवार 20 जनवरी, 2026

डाक पंजीयन संख्या: एफटीपी/एल/समाचार पत्र/2025-27/106

पृष्ठ 06 मूल्य 1.00 रुपया

## कांग्रेस की मांग, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोकने के मामले में हस्तक्षेप करें प्रधानमंत्री

(एजेंसी) नयी दिल्ली। कांग्रेस ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम में स्नान से कथित तौर पर रोकें जाने की निंदा करते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ट्रिपल इंजन सरकार पर एक संत का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि पूरा देश देख रहा है कि भाजपा के शासन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्ल श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, लेकिन एक शंकराचार्य के साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि यदि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हिंदुओं से माफी नहीं मांगते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह सनातनी नहीं, धनातनी हैं। खेड़ा ने कहा, नरेन्द्र मोदी 12 साल से सत्ता में हैं



कैसा सुलूक किया जा रहा है, यह दुनिया देख रही है। क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपराध यही है कि वह आपकी जय-जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं, आधे-अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताते हैं, महाकुंभ की कुव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कोविड के दौरान मां गंगा के आंचल में तैरती

लाशों पर बात करते हैं। उन्होंने दावा किया, सच्चाई यही है कि था, ये जो हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को सनातनी मत कहिए, आप धनातनी ही रहेंगे। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री हिंदुओं से माफी मांगेंगे? बीते रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थकों को संगम में जाने से कथित तौर पर रोकें जाने और विरोध करने पर कुछ समर्थकों की पिटाई किये जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना किसी अनुमति के 200–250 समर्थकों के साथ पुल नंबर दो का अवरोधक तोड़कर स्नान घाट की तरफ प्रवेश किया। वहीं, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगीराज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जगदगुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को प्रशासन ने जानबूझकर स्नान करने से रोका तथा यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी।

## आरएसएस-बीजेपी कुछ बिजनसमैनो के हाथों देश बेचना चाह रही,ये चाहते हैं कि लोग सवाल न करें, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी : राहुल

(एजेंसी) तिरुवनंतपुरम। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जनता सवाल न करें और चुप रहें, ताकि यह कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश को बेच सकें। राहुल केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करके पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर शासन को मजबूत किया। संविधान बचाने का मतलब है सत्ता और फैसलों का अधिकार लोगों तक पहुंचाना। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता को अपने पास

ही रखना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता को नीचले स्तर तक पहुंचाने में भरोसा रखती है



और गांव-कस्बों में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। दिल्ली में हुई बैठकों में अलग-अलग नेताओं की अलग राय थी, लेकिन मैंने साफ कहा था कि यूडीएफ

बड़ी समस्या है। यूडीएफ और कांग्रेस को ऐसा रोडमैप देना होगा, जिससे युवाओं को नौकरी मिले। मंच पर मौजूद नेतृत्व केरल की जनता की जरूरतों

को समझता है और उन्हें पूरा कर सकता है। इससे पहले राहुल ने एक कार्यक्रम में कलामासेरी में डॉ. एम लीलावती को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रियदर्शिनी साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि कोई भी देश अगर चुप रहता है तो वो महान नहीं हो सकता। चुप रहने की संस्कृति में लालच की भावना छुपी होती है। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र और महान लोग तब बनते हैं, जब वे अपने विचार और राय खुलकर व्यक्त करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। केरल कांग्रेस की महापंचायत के बीच स्टेज पर आकर एक बच्चे ने राहुल के साथ सेल्फी ली। इसके बाद बच्चे ने राहुल ने बच्चे के चॉकलेट भी दी।

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही एसआईटी को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताए गए अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद होगी।

## शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे से अनशन पर,बोले-माघ मेले में हर बार आऊंगा, लेकिन फुटपाथ पर रहूंगा

(एजेंसी) प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी



अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी

है। पालकी यानी रथ यात्रा रोकें जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं, जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 25 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। पानी तक छोड़ दिया। इस बीच

(एजेंसी) सुल्तानपुर। सूपी के सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 20 फरवरी को पेश होने का अंतिम मौका दिया है। यह मामला 8 साल पहले कर्नाटक चुनाव में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज किया था। कोर्ट ने व्यक्तिगत बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर हैं। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वादी का आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इस मामले में पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी के कोर्ट में

पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया



था।इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में उपस्थित हुए, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25–25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके तहत लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। केस करने वाले

भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया— 8 मई 2018 को बेंगलुरु में

कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, “अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचित्ता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।बता दें कि स्पेशल कोर्ट जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्त्त वह अपने एक साथी की

बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की एसआईटी जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने बताया था कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया था। विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को कोर्ट में तलब करने के पर्याप्त सबूत हैं।

## संजय राउत का दावा

### शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही

(एजेंसी) मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बना रही है। राउत ने कहा शिंदे अपने पार्षदों को पहले ही पांच सितारा होटल में भेज चुके हैं। सवाल है—कौन किससे डर रहा है? संजय राउत ने कहा नगर निकाय चुनावों के नतीजों को देखते हुए कोई भी पार्टी आसानी से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मेयर पद पर दावा नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री



फडणवीस रिव्टर्जरलैंड में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की बैठक में हैं और यहां पार्षदों को इधर-उधर भेजा जा रहा है। यह अजीब है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव हुए थे। बीएमसी सहित अन्य निगमों के नतीजे 16 जनवरी को आया था। बीएमसी के 227 सीटों में भाजपा ने 89 वाई जीते। शिंदे गुट को 29 सीटें मिलीं। मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है। इसके लिए भाजपा को शिंदे गुट के 25 पार्षदों के समर्थन की

जरूरत होगी। 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें यह तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित

जाति,जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद सात दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण मेयर चुनाव 29 या 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या 31 जनवरी को कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस 24 जनवरी को रिव्टर्जरलैंड से वापस आएंगे।

वर्कशॉप किया जा रहा है, ताकि उन्हें देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय बीएमसी के कामकाज की जानकारी दी जा सके। सूत्रों का कहना है कि हॉर्स-ट्रेडिंग को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। सभी 29 पार्षदों को 21 जनवरी दोपहर 3 बजे तक होटल में रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले 2017 में नगर निगम चुनावों के बाद अविभाजित शिवसेना ने 7 मनसे कॉर्पोरेटर का दलबदल करवाया था।

## कर्नल सोफिया कुरैशी केस: सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा, अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं

(एजेंसी) नयी दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के



भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक अभियोजन की मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं।मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अगस्त 2025 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और राज्य सरकार से अभियोजन (केस

चलाने) की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा

नियुक्त किया गया है। इस पर कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में दो पुराने मामलों का भी जिक्र है, उनमें एक नवंबर 2020 का और दूसरा उससे पहले का। हालांकि, इन मामलों को मौजूदा जांच में शामिल नहीं किया गया। सीजेआई ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय की कमी के कारण अगर उन मामलों को छोड़ा गया है तो एसआईटी को उम्मीद है कि वो उन आरोपों की भी जांच पूरी करेंगे। कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया कि एसआईटी) का गठन खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था और पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। रिपोर्ट के पैरा 10.2 में कुछ पुराने बयानों का जिक्र है, जिन्हें फिलहाल बाहर रखा गया। एसआईटी) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 217 के तहत राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजकर अभियोजन की पूर्व अनुमति मांगी थी, जो कि किसी मंत्री के खिलाफ कोर्ट द्वारा

संज्ञान लेने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, राज्य सरकार को कानून के मुताबिक अभियोजन की मंजूरी देने या न देने पर फैसला करना ही होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो दो हफ्ते के भीतर अभियोजन की मंजूरी पर फैसला लेकर अपनी

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही एसआईटी को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताए गए अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद होगी।

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही एसआईटी को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताए गए अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद होगी।

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही एसआईटी को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताए गए अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद होगी।

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही एसआईटी को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताए गए अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद होगी।

# सम्पादकीय

## ठाकरे भाइयों की पीड़ा हुई सर्वाजनिक

महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनावों में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। मैं नफीस जाफरी आपको यह बता दूँ कि उद्धव ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में बहुत सा पैसा खर्च किया है। उन्होंने प्रेशर कुकर बांटे, साड़ियां बांटी और बाकी चीजें भी बांटी। इस सबके लिए पैसा कहाँ से आया। ईडी, सीबीआई ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह उनकी पार्टी को तोड़कर उनके ही पार्टी नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसे ही भाजपा अब शिंदे की शिवसेना को तोड़कर बीएमसी में अपना महापौर बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि इस चुनाव में पैसे और मृतखोरी का व्यापक इस्तेमाल हुआ है। चुनाव से चार दिन पहले भारी मात्रा में पैसा बांटा गया था। लोगों को मिक्सर, वॉशिंग मशीन दी गई। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में बांटने के लिए ये बेहिसाब पैसा कहाँ से आया? क्या नोटबंदी नाकाम हो गई? उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लगभग सभी कुर्शियां खाली थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई उन्हें इतने दो मत मिले हैं, अगर मिले तो उन्हें किसने वोट दिए? खाली कुर्शियाँ ने? खाली कुर्शियां कैसे वोट दे सकती हैं शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने कहा कि हम मुंबई में अपना मेयर बनाना चाहते हैं और इस दिशा में काम करेंगे। चुनाव के ये नतीजे हमें कमजोर नहीं करते। हमारे उम्मीदवारों ने कड़ी मेहनत की थी और वे जीते भी हैं। बीएमसी चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना (उद्धव गुट) और राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना ने मराठी মানুষ की बात करते हुए कहा कि यह अभी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं राज ठाकरे ने भी मराठी মানুষ का ही जिक्र किया है। गौरतलब है कि पिछले तीन दशक से बीएमसी की सत्ता में काबिज रही शिवसेना इस बार महायुति से चुनाव हार गई है। बीएमसी में भाजपा को 89, शिवसेना (उद्धव) को 65, शिवसेना (शिंदे गुट) को 29 सीटें मिली हैं। शिवसेना (उद्धव) ने एक्स पर पोस्ट कर हार के बाद एक बार फिर मराठी মানুষ की बात ही है। पार्टी ने एक्स किए पोस्ट में लिखा है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मराठी মানুষ को जब तक उसका सही सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह ऐसे ही जारी रहेगी। इस पोस्ट में बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर लगी है। गौरतलब है कि इस बार पहली बार बीएमसी में भाजपा का मेयर होगा। भाजपा ये चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव की बागडोर संभाल ली थी। वहीं, राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि अगर मुंबई में मराठी মানুষ के साथ अत्याचार हुआ तो उनकी पार्टी किसी को छोड़ेगी नहीं। राज ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सर्वप्रथम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के सभी निर्वाचित पार्षदों को भेरी हार्दिक बधाई। इस बार का चुनाव आसान नहीं था। यह धन और सत्ता की शक्ति बनाम शिवसेना की शक्ति की लड़ाई थी। लेकिन ऐसे संघर्ष में भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर मुकाबला किया। उनकी प्रशंसा करने लायक कुछ खास नहीं है। यह दुख की बात है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन हम निराश होने वालों में से नहीं हैं। हमारे चुने हुए पार्षद मराठियों की हितों की रक्षा करेंगे। अगर किसी मराठी মানুষ के साथ अत्याचार होगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। गौरतलब है कि एमएनएस को बीएमसी चुनावों में केवल छह सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। बीएमसी चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन हुआ था। लेकिन चुनाव नतीजों ने दोनों को निराश किया है। वहीं बीएमसी की सत्ता में भाजपा का राज शुरू होने वाला है।

नफीस जाफरी



गुलफिशा खान

मुंबई का अगला महापौर कौन बनेगा। ऐसी चर्चा है कि इस पर फैसला जनवरी के अंत तक होगा। गौरतलब है कि बीएमसी चुनावों में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने बीएमसी में पिछले करीब तीन दशक से सत्ता में रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बेदखल कर दिया है। भाजपा ने बीएमसी में 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिवसेना (उद्धव) ने 65 वार्ड पर कब्जा किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 वार्ड पर जीत दर्ज की है। वहीं, कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीतकर अपनी

# एकनाथ शिंदे - बड़े पावर प्ले की रणनीति में जुटे

मौजूदगी दर्ज करवाई है। एआईएमआईएम को 8, मनसे को 6, एनसीपी को 3, सपा को 2 और एनसीपी शरद पवार को को 1 वार्ड मिला है। सूत्रों के मुताबिक अब महायुति महापौर बनाने की प्रक्रिया में जुट गई है। हालांकि, अभी इस पर सर्रप्से जारी है और इसके इस महीने के अंत तक खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगले सप्ताह नगर विकास विभाग महापौर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकालेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के ठीक दस दिन बाद महापौर का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस देशी के कारण अब यह स्पष्ट है कि जनवरी महीने के आखिरी दिनों में ही मुंबई को अपना नया महापौर मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। जैसा कि उल्लेखनीय है कि भाजपा 89 सीटों के साथ

सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन असली कहानी उन 29 सीटों में छिपी है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती है। आंकड़ों का गणित ऐसा उलझा है कि बिना शिंदे के धनुष—बाण के भाजपा का मेयर बनना नामुमकिन है। बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए। भाजपा के पास 89 सीटें हैं, यानी उसे अभी भी 26 और पार्षदों की जरूरत है, शिंदे की 29 सीटें ही भाजपा को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती हैं। शिंदे के पास अब वह ताकत है जिससे वह भाजपा से अपनी शर्तें मनवा सकें। शिंदे गुट के प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि मुंबई का मेयर शिवसेना (शिंदे) का होना चाहिए क्योंकि यह बालासाहेब की विरासत है। जहां एक ओर पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता शिवसेना का मेयर होने की मांग कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेहद सधा हुआ जवाब दिया है। शिंदे

ने कहा कि हमारा एजेंडा विकास है। हम महायुति के तौर पर लड़े

हैं। हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिंदे का यह



हैं और साथ बैठकर तय करेंगे कि मुंबई के हित में क्या बेहतर

नरम रुख एक बड़े पॉवर प्ले की रणनीति हो सकती है। तो सवाल

# असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों के नेता बन कर उभरे



फ़रीद वारसी

महाराष्ट्र और मुंबई नगरपालिका चुनाव में कई जगहों पर शानदार सफलता हासिल करने के बाद आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से खास बातचीत की। इस सफलता के लिए उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस जीत के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिम राजनीति पर भी खुलकर बात की। मालूम हो कि महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव नतीजों ने इस बार राज्य की राजनीति में एक अहम संकेत दिया है। यह संकेत है— ऑल इंडिया मजलिस—ए—इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लगातार और

रणनीतिक बढ़त का। सीमित संसाधनों, तीखे विरोध और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद एआईएमआईएम ने इन चुनावों में 126 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि पार्टी अब महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक स्थायी और प्रभावी ताकत बन चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि एआईएमआईएम ने 29 में से 12 महानगरपालिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो पार्टी के धीमे लेकिन स्थिर विस्तार की कहानी कहती है। एआईएमआईएम का सबसे शानदार प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व औरंगाबाद) महानगरपालिका में देखने को मिला, जहां पार्टी ने 33 सीटें हासिल कीं। यह परिणाम 2015 के चुनावों की तुलना में एक बड़ा उछाल है, जब एआईएमआईएम को यहां 24 सीटें मिली थीं। यानी पार्टी ने 9 सीटों की शुद्ध बढ़त दर्ज की। यह जीत केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह बताती है कि एआईएमआईएम ने यहां अपना सामाजिक आधार और संगठनात्मक पकड़ दोनों मजबूत की है। छत्रपति संभाजीनगर अब एआईएमआईएम के लिए सिर्फ एक नगर निगम नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। अगर दूसरे अन्य महानगरपालिकाओं

में एआईएमआईएम का प्रदर्शन की बात करें तो—छत्रपति संभाजीनगर— 33, मालेगांव — 21, नांदेड— 14,अमरावती — 12, धुले— 10, सोलापुर— 8, मुंबई — 8, नागपुर— 6, ठाणे—

महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील। उन्हें चुनावों से पहले पार्टी को सीट बंटवारे को लेकर आरोप, आंतरिक असंतोष और स्थानीय नेतृत्व के टकराव जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना



5, अकोला— 3, अहिल्यानगर— 2और जालना— 2। यह आंकड़े बताते हैं कि एआईएमआईएम का प्रभाव केवल मराठवाड़ा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई महानगर तक फैल चुका है। इन चुनावों में एआईएमआईएम की सफलता के केंद्र में रहे पूर्व सांसद और एआईएमआईएम

पड़ा। विरोधियों ने यहां तक दावा किया कि पार्टी भीतर से कमजोर हो रही है। लेकिन इम्तियाज जलील ने इन सभी चुनौतियों के बीच संगठन को एकजुट रखा। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को निर्णायक भूमिका दी, टिकट वितरण में सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी, शहरी मुद्दों (रोजगार, शिक्षा, बुनियादी

सुविधाएं) को केंद्र में रखा और नतीजा यह हुआ कि एआईएमआईएम ने विरोध और विवादों के बावजूद मैदान में बेहतर प्रदर्शन किया। इन चुनावों में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सक्रिय प्रचार भूमिका भी निर्णायक रही। ओवैसी की रैलियों और सभाओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। युवा और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जुटाने का काम किया। एआईएमआईएम को केवल विरोध की राजनीति से आगे ले जाकर स्थानीय शासन का विकल्प के रूप में पेश किया। विशेष रूप से मराठवाड़ा और मुंबई में उनकी सभाओं का सीधा असर वोट प्रतिशत और सीटों पर दिखाई दिया। मुंबई महानगरपालिका चुनाव एआईएमआईएम के लिए रणनीतिक सफलता साबित हुए। पार्टी ने यहां 8 सीटें जीतीं, जबकि 2017 के बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम को केवल 2 सीटें मिली थीं यानी इस बार 6 सीटों की सीधी बढ़त हुई है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई। वार्ड नंबर 134, 136, 137, 138, 139, 140, 143 और 145 से एआईएमआईएम की जीत ने यह साफ कर दिया कि पार्टी

अब मुंबई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विकल्प के रूप में उभर रही है। खास बात यह भी रही कि एआईएमआईएम मनसे से आगे निकल गई, जिसे बीएमसी में 6 सीटें मिलीं। यह तुलना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एआईएमआईएम की यह सफलता संकेत देती है कि शहरी मुस्लिम मतदाता अब पारंपरिक दलों से इतर विकल्प तलाश रहा है। ओवैसी श्रतीकात्मक राजनीतिश् से आगे बढ़कर स्थानीय सत्ता में भागीदारी की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने खुद को केवल विरोधी नहीं, बल्कि नगर प्रशासन में दखल रखने वाली ताकत के रूप में स्थापित किया है। हालांकि, विस्तार के साथ संगठनात्मक अनुशासन, नए वांछित पहुंच और गठबंधन राजनीति) लेकिन मौजूदा नतीजे यह साफ करते हैं कि एआईएमआईएम अब महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति में अनछेदी नहीं की जा सकने वाली शक्ति बन चुकी है। 2026 के महानगरपालिका चुनाव एआईएमआईएम के लिए केवल सीटों की जीत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है — एआईएमआईएम आई है, टिकने के इरादे से।

## बेरोजगारी का दंश

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें गत दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8 फीसदी होने की बात कही गई है। भारत दुनिया में युवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम इस युवा शक्ति का भरपूर उपयोग राष्ट्र विकास में नहीं कर पा रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि देश के शहरी क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से अधिक आयुवर्ग के युवाओं में बेरोजगारी की दर गांवों के मुकाबले ज्यादा है। जहां शहरों में यह प्रतिशत बढ़कर 6.7 फीसदी हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 3.9 फीसदी स्थिर है। हाल ही के वर्षों में बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा रहा है, जो भारत जैसे विकासशील देश के हित में नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास दर तभी सार्थक होगी, जब रोजगार के नये मौके उपलब्ध हो रहे हों। नीति—नियंताओं को आत्ममंथन करना होगा कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार के नये अवसर क्यों नहीं बन रहे हैं। सरकारें सुनिश्चित करें कि युवाओं को देश की तरक्की में योगदान देने का अवसर मिले। यदि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तो इसके मायने हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरी के मौके बढ़ नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में एआई और डिजिटलीकरण के चलते भी नौकरियां घटी हैं। तो क्या हम इस चुनौती के लिये अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं?निश्चित रूप से देश के नीति—नियंताओं को मंथन करना चाहिए कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'रिक्त इंडिया' जैसे अभियानों के जमीनी परिणाम उत्साहवर्धक क्यों नहीं हैं? युवाओं की कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के बावजूद रोजगार के मौके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समय के साथ कदमताल नहीं कर पा रही है? विडंबना यह भी है कि बढ़ती आबादी के बावजूद सरकारी क्षेत्र की नौकरियां कम हो रही हैं। युवाओं की शिकायत होती है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में तमाम तरह की विसंगतियां व्याप्त हैं। वे परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे हैं। निस्संदेह, बढ़ती बेरोजगारी हमारे विकास के मापदंडों पर भी सवाल खड़ी करती है। निश्चित रूप से संतुलित आर्थिक विकास की सार्थकता के लिए जरूरी है कि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़े तथा आर्थिक असमानता भी दूर हो। तेज विकास दर के साथ लोगों के जीवन में खुशहाली भी आनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ने से ही समाज में खुशहाली आ सकती है। जब देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो समाज में वास्तविक समृद्धि आ सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ने से उत्पादकता बढ़ेगी और महंगाई पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी। निस्संदेह, बढ़ती क्रय शक्ति भी अर्थव्यवस्था को गति देती है। निर्विवाद रूप से बेरोजगारी कम किए बिना हम देश के सौ साल पूरे होने तक विकसित भारत का लक्ष्य मुश्किल से हासिल कर पाएंगे। हमें एआई व डिजिटल चुनौती के मुकाबले के लिए युवाओं का कौशल विकास तेज करना चाहिए।

## कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद ने मेहताब आलम को विवेकानंद यूथ अवार्ड से नवाजा गया

राजस्थान के साहित्यिक एवं सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद ने मेहताब आलम को विवेकानंद यूथ अवार्ड से नवाजा गया है है। मेहताब आलम जोधपुर जिले से संबंधित हैं और साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे हैं। कथाकुंज साहित्यद्वय परिषद एक ऐसा सशक्त मंच है, जो नवांकुर रचनाकारों को परिवार, समाज और संस्कृति से जोड़ते हुए उनमें सामाजिक व साहित्यिक दायित्वों की भावना विकसित करता है। मेहताब आलम इससे पूर्व भी विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। वे समाज सेवा, सद्भावना, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक मूल्यों के सक्रिय संवाहक के रूप में जाने जाते हैं। अनेक साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक राजस्थानी संस्कृति के प्रचार—प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। परिषद को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में साहित्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कार्य तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा और गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों , सदस्यों एवं बेगम साहिबा नीलोफर नियाजी, अब्दुल दबीर,जेवा मुगीरुनिसन, और उरुज फातिमा अली जी ने मेहताब आलम को उनके नूतन 6विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए हार्दिक बधाई,मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं दीं। परिषद का मानना है कि उनकी नेतृत्व क्षमता, सक्रियता और संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता संगठन की गतिविधियों को प्रदेश में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहताब आलम का वक्तव्य ध्वार्ड पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मेहताब आलम ने कहा—“राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमे विवेकानंद यूथ अवार्ड से नवाजा गया है मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा तथा साहित्य और संस्कृति को जन—जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा।









